Rehabilitation package for flood affected people in Bihar

*224. SHRI GULAM RASOOL BALYAWI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government had promised to provide a rehabilitation package for the areas and the people affected by floods in Bihar in recent years;

(b) whether it is also a fact that this package has not been provided to the Government of Bihar so far,

(c) if so, the reasons therefor; and

(d) the action being taken to provide the package to Bihar at an early date?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) to (d) Yes, Sir. After the Kosi Floods in Bihar in 2008, the Ministry of Home Affairs provided an assistance of ₹ 497.35 crore under the Calamity Relief Fund and ₹ 117.21 crore from the National Calamity Contingency Fund for relief and immediate restoration works. Further, an assistance of ₹ 1732.80 crore was provided by the Ministry of Rural Development under Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Swarnajayanti Gram Swarojgar Yojana and Indira Awas Yojana. The Ministry of Drinking Water Supply provided an assistance of ₹ 239.69 crore for restoration of damaged drinking water supply system including 2nd installment under the Accelerated Rural Water Supply Programme. ₹ 88.53 crore was provided by the Ministry of Water Resources for restoration works. The Department of Food and Public Distribution made an allocation of 1.25 lakh tons of food grains at an estimated cost of ₹ 200.36 crore. The Ministry of Agriculture made a supply of wheat minikits and maize seeds at a cost of ₹ 11.77 crore. In addition, the Government of India in the Department of Economic Affairs facilitated an external assistance package amounting to a total of 220 miilion US Dollars for taking up the reconstruction and rehabilitation works after the Kosi Floods.

श्री गुलाम रसूल बलियावी : सर, बिहार में जो कोशी आपदा आई थी, उससे पूरे देश की जनता आहत हुई थी। उस समय तत्कालीन सरकार ने वहां के लोगों के पुनर्वास के लिए, इन्फ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए, नुकसान और तबाही के हिसाब से जो धन मुहैया करवाया, आज तक उसकी आपूर्ति नहीं हो सकी है। इसके कारण आज भी वहां की जनता को जो सहूलियतें देनी चाहिए, वे सहूलियतें हम उन्हें मुहैया नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसा इसलिए है

क्योंकि बिहार सबसे अधिक कमजोर राज्य है और आर्थिक एतबार से बहुत निचली सतह पर है। ...(**व्यवधान**)...

†**جناب غلام رسول بلیاوی :** سر، بہار میں جو کوشی آپدا آئی ہے، اس سے پورے دیش کی جنتا آہت ہوئی تھی۔ اس وقت کی سرکار نےوہاں کے لوگوں کے پنرواس کے لئے، انفراسٹرکچر ڈیولپمینٹ کے لئے، نقصان اور تباہی کے حساب سے جو دھن مہیّا کروایا، آج تک اس کی آپورتی نہیں ہو سکی ہے۔ اس کے کارن آج بھی وہاں کی جنتا کو جو سہولیتیں دینی چاہئیں، وہ سہولتیں ہم انہیں مہیّا نہیں کروا پا رہے ہیں۔ ایسا اس لئے ہے کیوں کہ بہار سب سے زیادہ کمزور راجیہ ہے اور آرتھک اعتبار سے بہت نچلی سطح پر ہے ...(مداخلت)...

सभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री गुलाम रसूल बलियावी : सर, इस संदर्भ में हम माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहते हैं कि आपदा से सम्बन्धित जो जवाब इन्होंने हमको दिया है, उस जवाब से मैं कतई संतुष्ट नहीं हूं। उनके लिए स्पैशल पैकेज दिए जाने का सवाल था। चूंकि मंत्री महोदय खुद वहां जाकर उनकी हालत देख चुके हैं, इसलिए हम माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहते हैं कि क्या आपदाग्रस्त लोगों के लिए इससे आगे का कोई स्टेप है या नहीं है?

†**جناب غلام رسول بلیاوی :** سر، اس سندربھ میں ہم مانئیے منتری مہودے سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ آپدا سے سمبندھت جو جواب انہوں نے ہم کو دیا ہے، اس جواب سے میں قطعی سنتشٹ نہیں ہوں۔ ان کے لئے اسپیشل پیکیج دئے جانےوالے کا سوال تھا۔ چونکہ منتری مہودے خود وہاں جاکران کی حالت دیکھ چکے ہیں، اس لئے ہم مانئیے منتری مہودے سے جاننا چاہتے ہیں کہ کیا آپدا گرست لوگوں کے لئے اس سے آگے کا کوئی اسٹیپ ہےیا نہیں ہے؟

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, 18 अगस्त, 2008 को कोशी नदी में बाढ़ आई थी, जिसके कारण बहुत बड़ी तबाही हुई थी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं हैं। माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा, उसका उत्तर देते समय अपनी तरफ से मैंने पूरा विवरण दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि तबाही से आहत उस क्षेत्र की जनता को राहत दिलाने के लिए जितना भी अधिक धन मुहैया कराया जा सकता था, उतना धन पहले ही मुहैया करवाया गया है। मैं माननीय सदस्य को यह जानकारी भी देना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो आर्थिक सहायता प्राप्त हुई थी, जो अभी तक खर्च हो जानी चाहिए थी, राज्य सरकार के द्वारा वह धनराशि अभी तक खर्च नहीं की गई है।

†Transliteration in Urdu Script.

सभापति महोदय, यदि माननीय सदस्य और अधिक जानना चाहेंगे और आपकी अनुमति होगी, तो मैं यह भी बताना चाहूंगा कि सरकार द्वारा तैयार वर्ल्ड बैंक की एक योजना थी, जिसकी कुल लागत लगभग 220 मिलियन अमरीकन डॉलर, यानी लगभग 1000 करोड़ रुपये के आसपास थी। लेकिन यह धनराशि भी अभी तक खर्च नहीं हो पाई है। एन.डी.आर.एफ., यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पॉस फोर्स, की तरफ से भी धनराशि जारी की गई है, जो 614.56 करोड़ रुपये है। साथ ही आपदा राहत निधि से 497.35 करोड़ रुपये जारी किए गए।

इसके अतिरिक्त भी सैंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कभी-कभी कुछ विशेष धन मुहैया कराने की आवश्यकता होती है, तो फाइनांस मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमिशन वह धन मुहैया कराते हैं। लगभग 117.21 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि से मुहैया कराए गए। इसी तरह बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज हैं, जिन्होंने कोशी रिवर में फ्लड आने के बाद अपना बहुत ही इम्पार्टेंट रोल प्ले किया है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने वहां बहुत कार्य किया है। साथ ही पेयजल आपूर्ति मंत्रालय, वॉटर रिसोर्सिज मिनिस्ट्री, फूड एवं पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इत्यादि ऐसी बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, जिन्होंने वहां की जनता को राहत दिलाने के लिए बहुत सारी धनराशि मुहैया कराई है।

श्री गुलाम रसूल बलियावी : सर, इस संदर्भ में जो भी पैकेज दिया गया है, या जो भी राहत दी गई है, तबही के हिसाब से वह राशि कुछ भी नहीं है। वहां पर दो-तीन जिलों को जोड़ने वाले करीब दो-तीन पुल हैं, जो आज भी क्षतिग्रस्त हैं और हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि फिर से हम उनको नया बना सकें।

हम माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि हमारे जो सांसद हैं, उनको समय दिया जाए और उस इलाके के पूरे तौर पर डेवलपमेंट के लिए किसी स्पेशल पैकेज की व्यवस्था की जाए। चूंकि, सर, आप अपनी आंखों से सब कुछ देख चुके हैं, वहां स्वयं जा चुके हैं, वहां एन.एच.-30 से मधेपुरा होते हुए सब हम सुपौल, सहरसा निकलते हैं, इस पूरी लाइन में रास्ते में जो बड़े-बड़े पुल आते हैं, आज भी वे सारे पुल डैमेज्ड हैं जब तक आपकी तरफ से कृपा नहीं होगी, तब तक हम कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे आशा रखता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इस पर माननीय सदन के माध्यम से मुझे कोई ठोस आवश्वासन देंगे।

†**جناب غلام رسول بلیاوی** : سر، اس سندربھہ میں جو بھی پیکج دیا گیا ہے، یا جو بھی راحت دی گئی ہے، تباہی کے حسابسے وہ راشی کچھہ بھی نہیں ہے۔ وہاں پردو-تین ضلعوں کو جوڑنے والے قریب دو-تین پل ہیں۔ جو آج بھی شرتی-گرہست ہیں اور ہمارے پاس اتنی شکتی نہیں ہے کہ پھر سے ہم ان کو نیا بنا سکیں۔

ہم مانننے منتری مہودے سے اگرہے کریں گے کہ ہمارے جو سنسد ہیں، ان کو وقت دیا جائے اور اس علاقے پورے طورپر ڈیولپمینٹ کے لئے کسی اسپیشل پیکیج کی ویوستھا کی جائے۔ چونکہ، سر، آپ اپنی آنکھوں سے سب کچھہ دیکھہ چکے ہیں، وہا خود جا چکے ہیں، وہاں این-ایچ-30 سے مدھے پورہ ہوتے ہوئے جب ہم سپول، سہرسہ

†Transliteration in Urdu Script.

نکلتے ہیں، ہم پوری لائن میں راستے میں جو بڑے بڑے پل آتے ہیں، آج بھی وہ سارے پل ڈیمیجڈ ہیں۔ جب تک آپ کی طرف سے کرپا نہیں ہوگی، تب تک ہم کوئی بہت بڑا کام نہیں کر پائیں گے۔ میں آپ سے آشا رکھتا ہوں کہ مائنے منتری مہودے اس پر مائنے سدن کے مادھیم سے مجھے کوئی ٹھوس آشواسن دیں گے۔

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि यह बाढ़ 2008 में आई थी। उस समय बाढ़ से राहत देने के लिए जो धनराशि मुहैया कराई गई थी, उसके अतिरिक्त 2009 के बाद सी.आर.एफ. (सेन्ट्रल रिलीफ फंड) के द्वारा भी 497 करोड़ की धनराशि मुहैया कराई गई है। साथ ही साथ, एन.सी.सी.एफ. के द्वारा भी 117 करोड़ की धनराशि मुहैया कराई गई है। इसके अतिरिक्त रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने, ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री ने वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्रीज ने भी अलग-अलग धनराशि मुहैया कराई है। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने वहां बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए और हर गांव में ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए धनराशि मुहैया कराई है। वह धनराशि लगभग 1732 करोड़ की है। ड्रिंकिंग वाटर मिनिस्ट्री ने वहां पर पेयजल की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए जो धनराशि मुहैया कराई है, वह एप्रॉक्सिमेटली 239 करोड़ है।

श्री सभापति : श्री हुसैन दलवई। सवाल बिहार फ्लड्स पर है। आप अपना सवाल पूछिए।

श्री हुसैन दलवई : महोदय, बिहार की स्थिति ऐसी है कि वहां 40 परसेंट जमीन पर या तो सूखा होता है या बाढ़ होती है। सरकार का एक 'इंटरलिंकिंग ऑफ रिवस प्रोजेक्ट' है. तो क्या इसमें बिहार के बारे में विचार किया जा रहा है?

श्री राजनाथ सिंह : सर, यह प्रश्न इंटरलिंकिंग ऑफ रि वर्स के बारे में है। वैसे भारत सरकार सिद्धांतत: पूरी तरह से सहमत है कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवस होना चाहिए और इस बार राष्ट्रपति महोदय, ने भी अपने अभिभाषण में उसकी चर्चा की है। यानी उससे हमारी भारत सरकार की मंशा पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार करना है और आगे कैसे प्रोसीड करना है, इसके सम्बन्ध में मैं समझता हूं कि जल्दी ही भारत सरकार अपनी कोई योजना तैयार करेगी।

SHRI D. RAJA: Sir, the answer explains how funds have been given from different Heads and from different schemes. My question is very specific, Sir. After the Kosi flood devastation, you as the Chairman of this august House had appealed to the Members of this House to contribute from their MPLAD funds. In the case of Leh and Ladakh also, you made a similar appeal. In the case of Uttarakhand devastation also, you made a similar appeal. Many of us have contributed to the relief work. How are these funds utilized? What is the mechanism that your Ministry has got to monitor how the funds given from Members' MPLAD funds are spent?

श्री राजनाथ सिंह : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में जो जानकारी चाही है, वह जानकारी मैं माननीय सदस्य को उपलब्ध करा दूंगा।

डा. अनिल कुमार साहनी : सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को यह जानकारी देना चाहता हूं कि अभी उन्होंने कहा कि जो पैसा दिया गया है, वह खर्च नहीं हुआ है, मगर वह खर्च हुआ है। पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह जी यहां बैठे हुए हैं। इन्होंने कहा था कि 1000 करोड़ रुपये देंगे, मगर कितना दिया? यह इनसे भी पूछिए।

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

डा. अनिल कुमार साहनी : सर, यह मेरा सवाल ही है। वहां पैसा खर्च किया गया, मगर वहां पैसा कम पड़ गया। वहां पर जितना खर्च के लिए चाहिए, वह पैसा कम पड़ गया। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि आप इसकी जांच करा लीजिए कि कितना पैसा कम पड़ा है और उसको दीजिए, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है। आप इसे विशेष राज्य दर्जा देने का काम कीजिए, ताकि हम उसे ठीक कर सकें। आप यह कब तक देंगे, इसका हमें आश्वासन दीजिए।

MR. CHAIRMAN: Thank you. Question No. 225.

Poor condition of ESI hospital in Bhubaneswar

*225. SHRI PYARIMOHAN MOHAPATRA: Will the Minister of LABOUR AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether Government is aware of the deplorable condition of the Employees' State Insurance (ESI) hospital in Bhubaneswar; and

(b) the steps, if any, being taken to resolve various deficiencies so that the workers covered under ESI and their families can get the best of treatment?

THE MINISTER OF LABOUR AND EMPLOYMENT (SHRI NARENDRA SINGH TOMAR): (a) and (b) A Statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) and (b) Employees' State Insurance (ESI) Hospital in Bhubaneswar, which is being run by the State Government of Odisha, is presently under up-gradation/renovation and, thus, is not fully functional.

Employees' State Insurance Corporation (ESIC) has taken up a project for up-gradation of the ESI Hospital, Bhubaneswar from 50 beds to 100 beds by renovating/ upgrading the existing block and by constructing a new block. The renovation/up-